मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2019-2020

जनसम्पर्क विभाग

www.mpinfo.org/www.mpnewsarch.org
www.dprftp.com &
District News Portal - www.dprmp.org

श्री संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव, जनसम्पर्क ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली।

मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2019-2020

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

विभागीय संरचना
कार्यालय

संचालनालय मुख्यालय	01	भोपाल
संभागीय कार्यालय	07	इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा
जिला कार्यालय	44	
राज्य के बाहर स्थापित कार्यालय	02	1. म.प्र. सूचना केन्द्र नई दिल्ली
		2. म.प्र. सूचना केन्द्र मुम्बई
विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उपक्रम/संस्था	02	1. मध्यप्रदेश माध्यम
		2. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

स्वीकृत पद

प्रथम श्रेणी	-	53
द्वितीय श्रेणी	-	78
तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	-	248 (20 सांख्येत्तर पदों सहित)
तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	-	232
चतुर्थ श्रेणी	-	251
कुल	-	**862**

विभागीय दायित्व

जनसम्पर्क विभाग का मुख्य दायित्व सरकार की नीतियों, निर्णयों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी प्रचार-प्रसार माध्यमों से लोगों तक पहुँचाना और जन-मानस में शासन की उज्ज्वल छवि प्रस्तुत करना है। विभाग की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

समाचार प्रभाग

इस प्रभाग द्वारा शासन की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों/योजनाओं/नीतियों और उनकी उपलब्धियों के समाचार, विशेष लेख, सफलता की कहानियाँ, फोटो कव्हरेज, वीडियो कव्हरेज आदि करवाए जाते हैं। इन्हें समाचार-पत्रों को प्रकाशन तथा दूरदर्शन तथा अन्य चैनलों को प्रसारण के लिये प्रतिदिन भेजा जाता है। साथ ही मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के प्रवक्ता के रूप में उनसे संबद्ध जनसम्पर्क अधिकारी उनका मीडिया संबंधी काम करते हैं।

वर्ष 2019 में जनवरी से दिसम्बर माह तक कुल समाचार 8909 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में समाचार जारी किये गये। साथ ही हिन्दी के 47 विशेष लेख/संदर्भ और अंग्रेजी के 25 लेख विभिन्न समाचार-पत्र/पत्रिकाओं को प्रकाशन के लिये जारी किये गये।

समाचार, विशेष लेख, संदर्भ और सफलता की कहानियाँ उर्दू और संस्कृत भाषा में अनुवाद कराकर वेबसाइट पर अपलोड की गईं। उर्दू समाचार, लेख आदि उर्दूभाषी समाचार-पत्रों को वितरित किये गये।

इसी प्रकार संभागीय/जिला जनसम्पर्क कार्यालयों द्वारा इस अवधि में लगभग एक लाख 26 हजार 875 समाचार स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशन के लिये भेजे गये।

प्रतिवेदित अवधि में मा. मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों, अन्य विभाग प्रमुखों के लिये समय-समय पर प्रेस ब्रीफिंग और पत्रकार-वार्ताओं का आयोजन भी किया गया।

प्रभाग द्वारा प्रतिवेदित अवधि में वर्ष 2019 के बजट सत्र के लिये राज्यपाल का अभिभाषण, 15 अगस्त के लिये मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संदेश, 26 जनवरी 2019 के लिये राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संदेश, मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 2019, ''विजय दिवस'' 15 दिसम्बर 2019 के लिये मुख्यमंत्री का संदेश और समय-समय पर मुख्यमंत्री के ब्लॉग तैयार किये गये। साथ ही विभागीय वेबसाइट की जानकारियों को समय-समय पर अद्यतन किया गया। स्वाधीनता दिवस, स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस-2019 के कव्हरेज, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यक्रमों के लिये समाचार-पत्र प्रतिनिधियों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रवेश-पत्रों का वितरण किया गया। सभी शासकीय आयोजनों के आमंत्रण-पत्र शाखा द्वारा मीडिया को वितरित किये गये। विशेष अवसरों पर समाचार-पत्रों में विशेष लेखों का प्रकाशन करवाया गया।

प्रभाग द्वारा जारी किये जाने वाले समाचारों में विविधता और नयापन लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस क्रम में प्राचीन धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व के पर्यटन स्थलों की जानकारी, साम्प्रदायिक सद्भाव, आसपास की घटनाओं, खेलों तथा योजनाओं पर आधारित समाचारों के अलावा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता पर आधारित समाचार भी प्रतिदिन ज्यादा संख्या में जारी किये जा रहे हैं।

लोकसभा निर्वाचन 2019 और झाबुआ विधानसभा उप निर्वाचन के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के कार्यालय में पत्रकार वार्ताओं के आयोजन के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी समाचार जारी किये गये। मीडियाकर्मियों को सभी 52 जिलों के निर्वाचन के मतदान एवं मतगणना प्राधिकार-पत्र जारी किये गये।

प्रतिवेदित अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य आयोगों के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का भी प्रभाग द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया।

संचार प्रभाग

प्रतिवेदित अवधि में विभाग की संचार प्रणाली को विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुदृढ़ किया गया। प्रचार-प्रसार तथा समाचारों/सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान में सुविधा की दृष्टि से 37 कम्प्यूटर, 14 लेपटॉप और 19 ऑल-इन-वन प्रिंटर को बदला गया।

इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनलों पर राष्ट्रीय/प्रादेशिक और स्थानीय स्तर के प्रसारित बुलेटिनों के दृष्टिगत् विभिन्न घटनाक्रमों/गतिविधियों संबंधी न्यूज़ की सतत् मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मुख्यालय में स्थापित मॉनिटरिंग सेल में 20 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय चैनलों के न्यूज़ बुलेटिनों और प्रदेश पर केंद्रित विशेष कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की गई, दिनभर की खबरों का प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री और विभिन्न स्तरों पर भेजा गया।

लोकसभा निर्वाचन 2019 में संपूर्ण टी.वी. न्यूज मॉनिटरिंग सेल को 20 कंप्यूटर सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के कार्यालय में निर्वाचन से संबंधित खबरों की मॉनिटरिंग के लिए शिफ्ट किया गया था, जहाँ सतत् 24×7 घंटे चार पारियों में चैनलों की मॉनिटरिंग की गई।

वेबसाइट

विभाग की मुख्य वेबसाइट www.mpinfo.org को नवीनतम टेक्नोलॉजी के अनुरूप नया स्वरूप दिया जाकर मोबाइल, टेबलेट और अन्य डिवाइस आधारित बनाया गया। इस साइट पर हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत सहित चार भाषाओं में समाचार/लेख आदि उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन जारी किये जाने वाले समाचार, जन-कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लेख, खुशियों की दास्तां, उम्मीदें रंग लाई-तरक्की मुस्कुराई, विजन टू डिलीवरी, माननीय मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के विजुअल्स, मंत्रिपरिषद् के निर्णय, साप्ताहिक मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण, मासिक मध्यप्रदेश संदेश, शासकीय विभागों की नीतियाँ, शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण अभियान, कला एवं संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक स्थलों की जानकारी, विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रदर्शन विज्ञापन, निविदा, अधिमान्यता, पत्रकार दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना, पत्रकार पुरस्कार योजना, मीडिया प्रतिनिधि कल्याण सहायता संबंधी नियम, अचल सम्पत्ति

के विवरण, नवीन सूचनाएं, विभागीय लोक सूचना एवं अपीलीय अधिकारियों की सूची, विज्ञापन के रिलीज ऑर्डर और सम-सामयिक संदर्भ के साथ ही मंत्रिपरिषद, प्रशासनिक अधिकारियों और विभाग के मुख्यालय तथा फील्ड अधिकारियों की सूची तथा विभिन्न विभागों के ई-मेल और पते उपलब्ध हैं।

साइट पर सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर एवं यू-ट्यूब) संबंधी विभागीय गतिविधियाँ भी प्रदर्शित हैं। अब यह साइट पहले से बेहतर और यूजर फ्रेन्डली हो गई है। साइट को प्रतिवेदित अवधि में 14 करोड़ 03 लाख 88 हजार 852 हिट्स प्राप्त हुए।

जिलों के समाचारों के लिये डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल www.dprmp.org कार्यरत है। पोर्टल पर जनवरी, 2019 से दिसम्बर 2019 की अवधि में 1 लाख 29 हजार 164 समाचार अपलोड केये गये। इस पोर्टल को प्रतिवेदित अवधि में 20 करोड़ 19 लाख 61 हजार 995 हिट्स प्राप्त हुए। राष्ट्रीय प्रादेशिक तथा स्थानीय समाचार-पत्र, पत्रिकाओं की क्लीपिंग देखने के लिये कार्यरत विभागीय वेबसाइट www.mpnewsarch.org को भी आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाकर यूजर्स फ्रेन्डली बनाया गया। इस साइट को भी प्रतिवेदित अवधि में 35 लाख 13 हजार 445 हिट्स मिले।

सोशल मीडिया

सोशल मीडिया के महत्व को समझते हुए जनसम्पर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया विंग का गठन किया गया है। वर्तमान में यह विंग रीयल टाइम में शासकीय समाचारों और गतिविधियों को लोगों तक पहुँचाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।

सोशल मीडिया विंग द्वारा वर्तमान में 435 सोशल मीडिया अकाउंट्स का संचालन किया जा रहा है, इनमें मुख्यमंत्री कार्यालय, जनसम्पर्क मध्यप्रदेश, 45 शासकीय विभाग, समस्त संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर, संभागीय एवं जिला जनसंपर्क अधिकारियों के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स शामिल हैं। जनसंपर्क विभाग के इंस्ट्राग्राम, लिंक्ड-इन और यू-ट्यूब चैनल का संचालन भी किया जा रहा है। प्रभाग के द्वारा 52 जनसंपर्क अधिकारियों के भी इंस्टाग्राम अकाउंट प्रतिवेदित अवधि में बनाये गये हैं।

विभाग के द्वारा प्रदेश में औद्योगिक निवेश की गतिविधियों के सोशल एवं डिजीटल मीडिया में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश का भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं लिंक्ड-इन अकाउंट्स का निर्माण किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण-2020(शहरी) के मद्देनजर स्वच्छ मध्यप्रदेश के भी 36 सोशल मीडिया अकाउंटस बनाए जाकर स्वच्छता के संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

विभागीय अधिकारी इस नई विधा में बेहतर तरीके से काम कर सकें, इसके लिए प्रतिवेदित अवधि में उन्हें प्रशिक्षित किया गया। विभाग के कार्यों में सोशल मीडिया के बेहतर उपयोग के लिए उपयोगितानुसार समय-समय पर ''ट्रेनिंग मॉड्यूल'' तैयार कराया जाकर उन्हें विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक जिला जनसम्पर्क कार्यालय में एक-एक सोशल मीडिया हैंडलर की व्यवस्था की गई।

प्रतिवेदित अवधि तक विभाग द्वारा संचालित सभी फेसबुक पेजों पर 19.07 लाख से अधिक लाइक्स और ट्विटर अकाउंट्स पर 17.16 लाख से अधिक फॉलोअर रहे। सोशल मीडिया विंग द्वारा प्रतिवेदित अवधि

में 03 हजार 226 ग्राफिक्स और 2000 से अधिक वीडियो प्रोजेक्ट्स तैयार किये गये, जिनका प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया अकाउंटस पर किया गया।

सोशल मीडिया प्रभाग को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। विभागीय प्लेटफॉर्म्स पर मुख्यमंत्री के कव्हरेज एवं सभी महत्वपूर्ण शासकीय कार्यक्रमों को LIVE करने के लिए LIVE U, कैमरा सेटअप और प्रोफेशनल wirecast software उपलब्ध कराया गया। इस संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्रतिवेदित अवधि में 800 से अधिक कार्यक्रमों को LIVE किया गया है।

सोशल मीडिया विंग द्वारा सप्ताह में पाँच दिन जनसम्पर्क ख़बरें', 10 संभाग-10 ख़बरें और जनसंपर्क बुलेटिन के नाम से बुलेटिन जारी कर शासन की गतिविधियों से लोगों को अवगत कराया गया। सभी विभागों के सोशल मीडिया प्लेटफार्म के लिए DPR Weekly Bulletin तैयार करना प्रारंभ किया गया जिसमें विभाग और विभागीय मंत्रीगणों की साप्ताहिक गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुँचाई गई।

शासन द्वारा लिये गये जनहितैषी निर्णयों एवं प्रदेश की जानकारी पर आधारित प्रत्येक शुक्रवार को Jansampark MP Quiz आयोजित किया गया। जनसम्पर्क के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 'क्या आप जानते हैं?' नाम से एक ग्राफिकल सेग्मेंट प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें जन हितैषी निर्णयों की जानकारी प्रचारित-प्रसारित की जा रही है। विभाग के सोशल मीडिया हैंडल्स पर 'Explore MP' नाम से भी ग्राफिकल सेग्मेंट प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से आम लोगों को मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

राज्य शासन के द्वारा लिये गये निर्णयों पर हितग्राहियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित वीडियो सेग्मेंट खुशियों की दास्तां सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नियमित रूप से प्रचारित-प्रसारित की जाती है। प्रतिवेदित अवधि में 247 खुशियों की दास्तां सोशल मीडिया अकाउंटस पर प्रसारित की गई।

जनसंपर्क के यूट्यूब चैनल पर 32 हजार से अधिक सब्स्क्राइबर प्रतिवेदित अवधि में रहे हैं जिसमें नियमित तैयार किये जाने वाले बुलेटिन, आयोजन विशेष पर तैयार किये जाने वाले स्पेशल वीडियो पैकेज, डिपार्टमेंट के कार्यों से संबंधित पैकेज अपलोड किये गये। इसके अलावा समय-समय पर इस चैनल में विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया गया है।

विभाग द्वारा युवाओं के लोकप्रिय रोजगारपरक साप्ताहिक समाचार-पत्र 'रोजगार और निर्माण' का ई-पेपर एडिशन वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। शासन संबंधी गतिविधियों की जानकारी देने वाली मासिक पत्रिका 'मध्यप्रदेश संदेश' भी ई-मैगजीन के रूप में विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा विभाग द्वारा प्रतिदिन के समाचारों पर आधारित 'जनसम्पर्क टुडे' नाम से ई-न्यूज लेटर जारी किया गया।

समस्त सोशल मीडिया अकाउंट्स को शामिल करते हुए www.jansamparkmp.com वेबसाइट भी तैयार की गई है। इस वेबसाइट पर प्रदेश के सोशल मीडिया नेटवर्क की पूरी जानकारी उपलब्ध है।

फोटो-फिल्म प्रभाग

प्रभाग द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण के अतिरिक्त अन्य सभी शासकीय कार्यक्रमों/आयोजनों/बैठकों के वीडियो/फोटो कव्हरेज तथा आवश्यकतानुसार छायाचित्रों के एलबम तैयार करवाये जाते हैं।

विभाग द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण एवं सभी शासकीय कार्यक्रमों/आयोजनों के वीडियो कव्हरेज करवाकर प्रतिदिन दूरदर्शन एवं अन्य स्थानीय टी.व्ही. चैनल को प्रसारण के लिये विभागीय वेबसाइट और यू-ट्यूब पर अपलोड किये जाते हैं। इस दौरान 1396 वीडियो कव्हरेज प्रसारण के लिये भेजे गये।

प्रतिवेदित अवधि में शासकीय कार्यक्रमों के फोटो कव्हरेज के छाया-चित्र वेब साइट और यू-ट्यूब पर अपलोड किये गये। संभागीय एवं जिला कार्यालयों के भी छायाचित्रों को विभिन्न सम चार-पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजा गया। इस अवधि में मुख्यालय द्वारा 1182 फोटो कव्हरेज करवाये गये।

फिल्म-निर्माण प्रभाग

फिल्म-निर्माण प्रभाग द्वारा प्रतिवेदित अवधि में कृषक प्याज प्रोत्साहन योजना, म.प्र. में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण, म.प्र. सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य, मिलावट मुक्त म.प्र., मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, म.प्र. सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, टाइगर स्टेट म.प्र., इंदिरा गृह ज्योति योजना, संपत्ति की गाइड लाइन दरों में 20 प्रतिशत की कमी, डेंगू की रोकथाम, महिलाओं के लिए अचल संपत्ति में भागीदारी हेतु स्टाम्प ड्यूटी 1100 रु. में, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, महिला सशक्तिकरण, जैविक खेती ने बदली तस्वीर, म.प्र. में खेल प्रतिभाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए नि:शुल्क ड्राइविंग लाइसेंस, मदर मिल्क बैंक, आदिवासियों का साहूकारों से लिया गया ऋण माफी योजना आदि पर केन्द्रित 44 वीडियो स्पॉट का निर्माण कर प्रादेशिक चैनलों पर प्रसारण करवाया गया है।

संदर्भ प्रभाग

संदर्भ प्रभाग में विभिन्न विषय विशेष की पुस्तकें उपलब्ध हैं। ये पुस्तकें समय-समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के ज्ञानवर्धन,पठन-पाठन तथा संदर्भ के उपयोग में आती हैं। शाखा द्वारा विभिन्न विषय-विशेष की चयनित पुस्तकें प्रदेश भर के जिला एवं संभागीय जनसम्पर्क कार्यालयों एवं नई दिल्ली/मुम्बई स्थित सूचना केन्द्रों को संदर्भ के लिए भेजी जाती हैं। लोक सेवा के रूप में न्यू मार्केट स्थित जी.टी.बी.कॉम्पलेक्स में सूचना केन्द्र संचालित है। नि:शुल्क संचालित यह सूचना केन्द्र प्रतिदिन दोपहर 02:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक आमजन के लिए खुला रहता है।

वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संदर्भ प्रभाग की लायब्रेरी का कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया है । इसी क्रम में लायब्रेरी की लगभग 13 हजार पुस्तकों की बार कोडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। डिजिटाइजेशन से दुनियाभर में कहीं पर भी संदर्भ शाखा की वेबसाइट www.dprlib.com पर पुस्तकों की उपलब्धता देखी जा सकेगी। शेष कार्य भी प्रगति पर है ।

पाठकों को लायब्रेरी में पढ़ने योग्य उचित माहौल उपलब्ध कराने के लिए लायब्रेरी के रिनोवेशन का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है ।

विज्ञापन प्रभाग

विज्ञापन प्रभाग द्वारा राज्य शासन के सभी विभाग/कार्यालय की निर्माण/निविदा/ भर्ती सूचनाओं का समाचार-पत्रों में विज्ञापन के रूप में प्रकाशन करवाने का कार्य किया जाता है।

इसके अतिरिक्त राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का प्रदर्शन विज्ञापन के माध्यम से प्रिंट मीडिया एवं न्यूज कैप्सूल/वीडियों स्पॉट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार-प्रसार करवाने के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी इस प्रभाग द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत दूरदर्शन/आकाशवाणी, विविध भारती, टी.वी. न्यूज चैनलों, प्राइवेट रेडियो और एफ.एम. चैनलों, कम्युनिटी रेडियो, वेबसाइट/वेबपोर्टल, सिनेमा और मल्टीप्लेक्स के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों का प्रसार-प्रसार कराया गया। विशेष रूप से जय किसान फसल ऋण माफी योजना, युवा स्वाभिमान योजना, मैग्रीफिसेंट म.प्र. तथा शासन की एक वर्ष की उपलब्धियों का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप मतदाता जागरूकता संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन एवं वीडियो स्पॉट का प्रसारण भी कराया गया है।

पारदर्शिता और सुगमता की दृष्टि से वर्गीकृत तथा प्रदर्शन विज्ञापन सामग्री और विज्ञापन आदेश ऑनलाइन जारी किये जाते हैं। विज्ञापन प्रभाग द्वारा विज्ञापन देयकों के ऑनलाइन भुगतान के साथ ही विज्ञापन आदेश एवं विज्ञापन सामग्री भी ऑनलाइन दी जा रही है। इसको और अधिक उन्नत करते हुए विभिन्न विभागों एवं पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशकों तथा चैनलों से आवेदन लेने तथा विज्ञापनों के देयक ऑनलाइन बुलाने के लिए कम्प्यूटर प्रणाली को विकसित किया जा रहा है।

कैलेण्डर वर्ष 2019 में कुल 15,102 विज्ञापन जारी किये गये। इनमें 14,047 वर्गीकृत और 1,055 प्रदर्शन विज्ञापन शामिल हैं।

प्रकाशन प्रभाग

जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रकाशन राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी, नीतियों और कार्यक्रमों का आईना होते हैं। प्रदेश की लोकहितकारी नीतियों, योजनाओं और प्रदेश के जीवन तथा समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशनों का कार्य संचालनालय की प्रकाशन शाखा द्वारा किया जाता है। इन प्रकाशनों में किताबें, लघु पुस्तिकाएं, फोल्डर, पेम्फलेट्स और पोस्टर तथा मासिक पत्रिका मध्यप्रदेश संदेश शामिल हैं।

मध्यप्रदेश संदेश

प्रदेश सरकार की आमुख पत्रिका मध्यप्रदेश संदेश हर माह प्रकाशित होने वाली नियमित पत्रिका है। संदेश का प्रत्येक अंक एक समयानुकूल आवरण कथा पर केन्द्रित किया जा रहा है। पत्रिका में मुख्यत: प्रदेश की जन-कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और उनके परिणामों पर केन्द्रित सामग्री प्रकाशित की जाती है। पत्रिका को नये कलेवर के साथ प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों पर विशेष लेखों का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अलावा इस पत्रिका में

प्रदेश की विशिष्टताओं, विभिन्नताओं और विलक्षणताओं पर तथा प्रदेश के जीवन और समाज, कला, साहित्य, संस्कृति, पर्व, तीज-त्यौहार, परम्पराओं, लोक जीवन, वन और वन्य-जीवन, पर्यटन, खेल, सिनेमा तथा साहित्यिक गतिविधियों और प्रदेश से जुड़े विशिष्ट व्यक्तित्वों एवं विकास की विभिन्न अवधारणाओं पर वरिष्ठ और युवा लेखकों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

लोकहित कार्यों पर प्रकाशन

मध्यप्रदेश सरकार के जन-कल्याणकारी कार्यों की जानकारियाँ दूर-सदूर गाँवों में रहने वाले लोगों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न प्रकाशन किए गए। इन प्रकाशन को जिला मुख्यालयों पर स्थित जनसंपर्क कार्यालयों के माध्यम से जन-सामान्य तक पहुँचाया गया है। इसके अलावा ऐसे विशिष्ट आयोजनों में इन प्रकाशनों का वितरण किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में जन-समुदाय उपस्थित था।

प्रदेश सरकार ने जिन गरीबों, शोषितों, पिछड़ों तथा वंचितों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी योजनाओं की जानकारी देने और लाभ लेने के सुलभ तरीकों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाने वाली पुस्तिका- आगे आयें लाभ उठायें का नया संस्करण प्रकाशन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा वर्ष 2019-20 में बदलाव के लिए संकल्पित 76 दिन में 86 वचन पूरे फोल्डर, मध्यप्रदेश सरकार के छः माह-बदलाव का पहला पड़ाव, हमारी सरकार-भरोसे की सरकार-365 दिन में 365 वचन पूरे, मध्यप्रदेश और गाँधी जी पुस्तक, कमल नाथ सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों पर पुस्तक उम्मीदें रंग लाईं-तरक्की मुस्कुराई, मध्यप्रदेश सरकार के 100 निर्णय, गौ-शालाएँ फोल्डर, विजय दिवस पर भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय फोल्डर एवं विजन डिलीवरी रोडमैप 2020-2025 पुस्तक और प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों पर केन्द्रित 'मध्यप्रदेश संदेश' के विशेषांक का प्रकाशन किया गया।

पत्र-परिनिरीक्षण प्रभाग

पत्र-परीनिरीक्षण प्रभाग में मुख्य रूप से स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, सांध्यकालीन समाचार-पत्रों की कतरनों के बंच तैयार कर शासन के प्रमुख स्तरों पर प्रेषित करने का कार्य किया जाता है। प्रभाग द्वारा जनवरी से दिसम्बर, 2019 की अवधि में लगभग 106 लाख 47 हजार 959 समाचार कतरनें विभिन्न स्तरों यथा राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जनसंपर्क, माननीय समस्त मंत्रीगण, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, सभी प्रमुख सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित निर्देशानुसार अन्य स्तरों पर प्रेषित की गई।

प्रभाग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 की अधिसूचना अवधि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के कार्यालय में पृथक समाचार-पत्र परिनिरीक्षण प्रकोष्ठ स्थापित कर निर्वाचन संबंधी समाचार कतरनों को शीघ्रता से उपलब्ध कराने का कार्य भी किया गया।

दिल्ली से आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों के ई-पेपर में प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण समाचारों के परिनिरीक्षण का कार्य भी प्रभाग के वेबसाइट कक्ष में संपादित किया गया।

प्रतिवेदित अवधि में प्रभाग द्वारा उच्च स्तरों से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित संदर्भ कतरनों को तत्परता पूर्वक समय-सीमा में उपलब्ध कराने का कार्य भी संपादित किया गया।

पंजीयन प्रभाग

पंजीयन प्रभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों से प्रकाशित हो रहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार-पत्रों के साथ ही मासिक, त्रैमासिक तथा अन्य नियतकालिक पत्र-पत्रिका को एक वर्ष तक जिलेवार संधारित किया जाता है ।

कालखण्ड माह जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक 498 दैनिक समाचार-पत्र, 965 साप्ताहिक समाचार-पत्र, 104 पाक्षिक पत्र/पत्रिका, 1012 मासिक पत्र/पत्रिका एवं 80 त्रैमासिक पत्र/पत्रिका पंजीयन शाखा में प्राप्त हुए है।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

क्षेत्र प्रचार प्रभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ विकासात्मक उपलब्धियों एवं कार्यक्रम को आमजन तक पहुँचाने के लिए आउटडोर ब्रांडिंग एवं आधुनिक जनसंचार के माध्यमों से निम्नानुसार प्रचार-प्रसार किया गया।

- जय किसान फसल ऋण माफी योजना का विकासखण्डवार प्रचार-रथ, होर्डिंग्स एवं नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रचार-प्रसार किया गया।
- विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी बाहुल्य जिलों के 89 विकासखण्डों एवं शेष 32 जिलों में प्रदर्शनी पैनल्स के द्वारा ब्रांडिंग की गई।
- विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा एवं झाबुआ में प्रदर्शनी लगाई गई।
- संत समागम कार्यक्रम का भोपाल शहर में प्रचार-प्रसार किया गया।
- गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के 13 जिलों में महात्मा गांधी की मध्यप्रदेश यात्रा की प्रदर्शनी लगाई गई।
- मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 इंदौर के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न 15 विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई।
- मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश-2019 की इंदौर शहर सहित देश के बड़े मेट्रो शहरों में एयरपोर्ट एवं बोर्डिंग पास पर ब्रांडिंग की गई।
- झाबुआ में जय किसान कृषक समृद्धि योजना कार्यक्रम, मोनिया महोत्सव, फिल्म फेस्टिवल खजुराहो, जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी एवं ब्रांडिंग की गई।
- 64वें मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर समस्त जिलों में प्रदर्शनी लगाई गई।
- 16 दिसंबर को विजय दिवस कार्यक्रम के अवसर पर शौर्य स्मारक एवं रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी लगाई गई।
- गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर अक्टूबर माह से प्रदेशव्यापी गांधी यात्रा का संचालन किया जा रहा है।
- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई।

अधिमान्यता

अधिमान्यता नियम के अनुसार पत्रकारों को राज्य/जिला एवं तहसील स्तरीय अधिमान्यता प्रदान की जाती है। इसके लिये राज्य तथा संभागीय अधिमान्यता समितियाँ गठित हैं। प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार इन समितियों के सदस्य होते हैं। राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति पत्रकारों के राज्य स्तरीय अधिमान्यता और संभाग स्तरीय अधिमान्यता समिति पत्रकारों के जिला एवं तहसील स्तरीय अधिमान्यता संबंधी प्रकरणों में अनुशंसा करती है। वर्ष 2017 से अधिमान्यता कार्ड के नवीनीकरण/नवीन अधिमान्यता के लिये आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जा रहे हैं । मध्यप्रदेश में दिसंबर 2019 की स्थिति में 1124 राज्य स्तरीय, 1947 जिला स्तरीय एवं 822 तहसील स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं।

पत्रकारों को आर्थिक सहायता

पत्रकारों को स्वयं एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार के लिए पात्रता और आवश्यकता के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इसके लिए मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति गठित है। प्राप्त सहायता आवेदनों पर समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार सहायता की कार्रवाई की जाती है। इसके तहत् सामान्य बीमारियों के लिये 20 हज़ार रुपये तक एवं गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु अधिकतम 50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक 425 पत्रकारों को 1,32,55,000/- रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उन पर आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देने की अधिकतम सीमा राशि 4.00 लाख रुपये की गई है। इसके तहत् वित्तीय वर्ष 2019-20 में दिसंबर माह तक 17 दिवंगत पत्रकारों के परिवारजनों को 37.00 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है ।

अनुदान

- वर्ष 2019-20 में माधवराव सप्रे समाचार-पत्र संग्रहालय,भोपाल को 10.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

फैलोशिप

- स्व. राजेन्द्र माथुर स्मृति पत्रकारिता फैलोशिप के अर्न्तगत प्रतिवर्ष एक पत्रकार को एक लाख रुपये की राशि देने का प्रावधान है।

पत्रकारिता सम्मान

मध्यप्रदेश में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिये उत्साहजनक वातावरण बनाये जाने और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अग्रणी पत्रकारों को सम्मानित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्रकारिता सम्मान प्रारम्भ किये गये हैं। वर्ष 2016 तक के यह सम्मान वितरित किये जा चुके हैं। पत्रकारों को विशिष्ट योगदान के लिये सम्मानित करने के उद्देश्य से नीचे दर्शाये अनुसार सम्मान स्थापित किये गये हैं :-

राष्ट्रीय सम्मान (सम्मान राशि 2.51 लाख रुपये)

1. माणिकचन्द्र बाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान (एक)
2. गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान (एक)
3 विद्यानिवास मिश्र राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान (एक)

राज्य स्तरीय सम्मान (सम्मान राशि 1.51 लाख रुपये)

1. महेन्द्र चौधरी राज्य स्तरीय (फोटो) पत्रकारिता सम्मान (एक)
2. सत्यनारायण श्रीवास्तव, राज्य स्तरीय पत्रकारिता सम्मान (एक)

आंचलिक पत्रकारिता सम्मान (सम्मान राशि 1.01 लाख रुपये) (सात)

1.	स्व. शरद जोशी सम्मान	भोपाल अंचल के पत्रकारों के लिये
2.	स्व. राहुल बारपुते सम्मान	इंदौर अंचल के पत्रकारों के लिये
3.	स्व. बनारसीदास चतुर्वेदी सम्मान	रीवा अंचल के पत्रकारों के लिये
4.	स्व. रतनलाल जोशी सम्मान	ग्वालियर अंचल के पत्रकारों के लिये
5.	स्व. जीवनलाल वर्मा विद्रोही सम्मान	जबलपुर अंचल के पत्रकारों के लिये
6.	स्व. कन्हैयालाल वैद्य सम्मान	उज्जैन अंचल के पत्रकारों के लिये
7.	स्व. मास्टर बलदेव प्रसाद सम्मान	सागर अंचल के पत्रकारों के लिये

मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय टेलीविज़न पत्रकारिता सम्मान

राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रानिक चैनल के पत्रकारों एवं कैमरामेन के सम्मान के लिये भी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1.	राष्ट्रीय न्यूज चैनल (पत्रकार) सम्मान	राशि 1.51 लाख रुपये (एक)
2.	राष्ट्रीय न्यूज चैनल (कैमरामेन) सम्मान	राशि 1.01 लाख रुपये (एक)
3.	राज्य स्तरीय न्यूज चैनल (पत्रकार) सम्मान	राशि 1.51 लाख रुपये (एक)
4.	राज्य स्तरीय न्यूज चैनल (कैमरामेन) सम्मान	राशि 1.01 लाख रुपये (एक)

सम्मान-निधि

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान-निधि की राशि 7 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपये तथा आयु सीमा 62 से घटाकर 60 वर्ष की गई। वर्तमान में 177 पत्रकारों को 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह सम्मान-निधि प्रदान की जा रही है।

लेप-टाप

शासन द्वारा राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लेपटॉप देने की योजना संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में दिसम्बर 2019 की स्थिति में राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लेपटॉप क्रय करने के लिये राशि का भुगतान किया जा रहा है।

संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

शासन द्वारा मध्यप्रदेश के संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना में स्वास्थ्य बीमा 2.00 एवं 4.00 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 5.00 लाख एवं 10.00 लाख रुपये का है। योजना में दिसम्बर 2019 तक 2851 संचार प्रतिनिधि का बीमा हो चुका है।

पत्रकार प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश के जिलों/तहसीलों में पत्रकारों के लिये मीडिया संवाद कार्यक्रम'' का आयोजन किया जा रहा है। मीडिया संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य मध्यप्रदेश के जिलों में कार्यरत पत्रकारों को पत्रकारिता के कौशल बारीकियों पर चर्चा कर उन्हें नवीन तकनीक, प्रेस एक्ट और संविधान में उल्लेखित प्रेस से जुड़े कानूनों से परिचित कराना है । इस वर्ष विकास का एक वर्ष जन सरोकार और मीडिया'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

आवास ऋण ब्याज अनुदान

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिमान्य पत्रकारों को 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 5% ब्याज अनुदान 05 वर्ष तक दिये जाने की योजना का क्रियान्वयन किया गया है।

नवीन अभिनव कार्य योजना

आर्थिक सहायता

- पत्रकारों को एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को शामिल किया गया है।

बीमा योजना

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना में इस वर्ष से नियमित योजना राशि के साथ विकल्प स्वरूप 4.00 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10.00 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा शामिल किया गया है।

विश्व-स्तरीय मीडिया सेंटर

भोपाल स्थित मालवीय नगर में विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया सेंटर के निर्माण की दिशा में तेज़ी से पहल की जा रही है। मीडिया सेंटर के निर्माण में वरिष्ठ पत्रकारों के सुझाव लेने के लिये 10, जनवरी 2020 को बैठक आयोजित की गई।

मध्यप्रदेश माध्यम

मध्यप्रदेश माध्यम की स्थापना जन-संचार के क्षेत्र में तेजी से होते बदलावों और नये समय में संचार की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से जनसंपर्क विभाग के सृजनात्मक उपक्रम के रूप में हुई है।

पिछले दो दशकों से अधिक समय से मध्यप्रदेश माध्यम, राज्य सरकार और उसकी संस्थाओं के लिये संचार की सभी विधाओं में कार्य कर रहा है एवं आधुनिक समय के अनुरूप प्रचार कार्यों को नयी शक्ल देने में कामयाब रहा है। यह संस्था युवाओं के लिये साप्ताहिक रोजगार और निर्माण के प्रकाशन के साथ शासकीय विभागों के लिये विभिन्न प्रकाशन और फिल्मों का निर्माण भी करता है।

''रोजगार और निर्माण'' मध्यप्रदेश माध्यम से प्रकाशित होने वाला नियमित साप्ताहिक समाचार-पत्र है। इसकी लगभग 60 हजार प्रतियाँ प्रति सप्ताह प्रकाशित होती हैं। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों तक यह समाचार-पत्र पहुँचता है। इस समाचार-पत्र के प्रकाशन की नियमितता और गुणवत्ता के कारण इसकी एक विशिष्ट पहचान बनी है।

संचार के इस समय में ग्रामीण संचार की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मासिक पत्रिका मध्यप्रदेश पंचायिका का प्रकाशन भी पिछले दो दशक से मध्यप्रदेश माध्यम कर रहा है।

वर्ष 2020 के शासकीय कैलेण्डर का विशेष स्वरूप में आकल्पन किया गया। संस्था द्वारा विशेष मीडिया कैम्पेन्स, इवेंट मैनेजमेंट, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है।

संस्था के वर्ष 2018-19 तक के अंतिम लेखे तैयार कर चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स द्वारा अंकेक्षण किया जा चुका है। संस्था का वर्ष 2016-17 तक के लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार कार्यालय, ग्वालियर द्वारा भी किया जा चुका है।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का उद्देश्य हिन्दी पत्रकारिता पर विशेष फोकस के साथ इसे पत्रकारिता जनसंचार प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में अध्यापन प्रशिक्षण और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रुप में विकसित करना है। तेजी से विस्तार पा रहे प्रिन्ट और प्रसारण मीडिया को योग्य और प्रशिक्षित पत्रकार उपलब्ध कराना हिन्दी और अन्य भाषायी पत्रकारिता के बीच अंतर-संवाद स्थापित करना पत्रकारिता के सामाजिक सरोकारों पर विमर्श और संवाद पत्रकारिता एवं संचार के विविध आयामों पर उत्कृष्ट शोध गतिविधियों का संचालन इसके प्रमुख लक्ष्य हैं।

मुख्यालय भोपाल के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के तीन अन्य परिसर क्रमशः नोएडा खण्डवा एवं रीवा में संचालित हैं। मुख्यालय स्थित शैक्षणिक विभागों में 25, नोएडा परिसर में 4 तथा कर्मवीर विद्यापीठ, खण्डवा में 5, रीवा परिसर में 3 पाठ्यक्रम संचालित हैं। देशभर में विश्वविद्यालय की 62 मीडिया व 865 कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों की सहयोगी अध्ययन संस्थाएं हैं।

परीक्षा विभाग

परीक्षा विभाग के अंतर्गत नामांकन शाखा द्वारा जनवरी 2019 में कुल 33,925 विद्यार्थियों एवं सत्र जुलाई, 2019 में 86,284 इस प्रकार कुल 1,20,209 विद्यार्थियों के नामांकन जनरेट किये गये हैं।

पत्रकारिता विभाग

विशेष पाठ्यक्रम

एम.जे. पाठ्यक्रम को जुलाई-2019 से परिवर्तित कर एम.ए.जे. के शीर्षक से संचालित किया जा रहा है।

न्यूज रूम का निर्माण

- प्रत्येक सप्ताह विशेष विषय पर विद्यार्थियों द्वारा अपने-अपने आलेख के साथ समाचार-पत्र विकल्प निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
- विभाग द्वारा संचालित एम.ए. (डिजिटल जर्नलिज्म) पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों द्वारा वीडियो प्रोडक्शन व लाइव कवरेज विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किया जा रहा है।

प्लेसमेन्ट प्रकोष्ठ

कैम्पस प्लेसमेंट के अन्तर्गत Zee News, Etv Bharat Network 18, सहारा इंडिया, Jaro Education, वेब दुनिया, सार्थक टी.वी., Aglasem Edutech Gurgaon, Crazy Media Labs, लोकनीति चैनल, TV 9, Onliy Profit India, Amcosons, Duta, Hospibuz तथा दैनिक भास्कर भोपाल द्वारा केम्पस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त कई विजिट आयोजन करवाये गए। विभिन्न मीडिया एवं कम्प्यूटर संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। इस वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का चयन इन कंपनियों के अतिरिक्त कई अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ।

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

विज्ञापन एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा 09, 10 एवं 11 सितम्बर 2019 में इम्प्रेस एवं आईसीएसएसआर के सहयोग से तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमीनार 'International conference on Digital Communicatin : A Challenge for Developing Nations' का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में देश-विदेश के प्रतिभागियों ने अपने पेपर प्रस्तुत किये।

मीडिया प्रबंधन विभाग

मीडिया प्रबंधन में विद्यार्थियों के कैम्पस प्लेसमेंट आयोजित हुए। इसमें Jaro Education, वेब दनिया, Zee News, Etv Bharat Network 18, सहारा इंडिया, Aglasem Edutech Gurgaon, सार्थक टी.वी., Crazy Media Labs, लोकनीति चैनल, Tv 9, Onliy Profit India, Amco sons, Duta, Hospibuz जैसे संस्थानों ने भागीदारी कर विद्यार्थियों का चयन किया।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग

इस विभाग में प्रसारण गुणवत्ता उपकरणों पर विद्यार्थियों को कौशल विकास का अभ्यास कराया गया।

प्रशिक्षण - इस विभाग के छात्र-छात्राओं को ई-टी.वी. न्यूज चैनल हैदराबाद, एबीपी न्यूज नोएडा, इंडिया न्यूज भोपाल, आई.बी.सी-24 भोपाल, कशिश न्यूज चैनल रांची, झारखंड हिन्दी खबर नोएडा, जैसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों एवं विभिन्न न्यूज पोर्टल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

प्रकाशन विभाग

(अ) मनुज फीचर सर्विस

विश्वविद्यालय की बहुउपयोगी मनुज फीचर सर्विस का प्रकाशन पुनः आरंभ किया गया। विभिन्न सम-सामयिक विषयों पर पत्रकारिता के विद्यार्थियों, वरिष्ठ पत्रकारों, साहित्यकारों एवं प्रबुद्धजनों द्वारा आलेख लिखे गये। अभी तक विभिन्न विषयों पर 71 आलेख जारी किये गये।

(ब) प्रकाशित पुस्तकें

1. कबीर वाणी में संचार पद्धति/परंपरा - श्री साकेत दुबे
2. चुनाव और लोक विमर्श, शोध प्रतिवेदन - डॉ. पवित्र श्रीवास्तव

(स) प्रकाशनाधीन पुस्तकें

1. समाज विज्ञान, संचार एवं प्रबंधन में अनुसंधान कौशल विकास - डॉ. बी.एस.नागी/डॉ. ए.एम.खान
2. जनसंपर्क एवं निगमित संचार - डॉ. नीमोधर

(द) कैलेण्डर का प्रकाशन

स्वतंत्रता संग्राम के जननायकों एवं पत्रकारिता के प्रमुख स्तम्भों पर केंद्रित कैलेण्डर का प्रकाशन किया गया। कैलेण्डर के माध्यम से एक ओर जहाँ स्वतंत्रता संग्राम में जन नायकों के योगदान को दर्शाया गया वहीं

दूसरी ओर बाबासाहब आम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया ।

कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभाग

1. एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं एम.एससी. (आई.सी.एस.) के विद्यार्थियों के लिये Android Application Development विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला की गई।
2. विभाग में एम.सी.ए., बी.सी.ए., एम.एससी. (आई.सी.एस.) के विद्यार्थियों के लिये Cloud Computing विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला की गई।
3. ICT for Excellence विषय पर विभाग में दो दिवसीय सेमीनार किया गया।
4. संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के शिक्षकों के लिए Linux विषय पर अध्ययन संस्थाएं विभाग एवं कम्प्यूटर विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से Faculty Development Programme का आयोजन किया गया।

जनसंचार विभाग

- मध्यप्रदेश स्थापना दिवस- 01 नवंबर के अवसर पर विभाग में नये मीडिया न्यूज रूम की स्थापना की गई।

एन.सी.सी. यूनिट

विश्वविद्यालय में एन.सी.सी. ट्रुप (यूनिट) में कुल एक प्लाटून संख्या (संख्या 54 SD/SW 3 वर्षीय) में प्रथम वर्ष में 29 द्वितीय वर्ष में 13 एवं तृतीय वर्ष में 05 कैडेट्स पंजीकृत हैं। कुल 47 कैडेट्स नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यूनिट के 2 कैडेट्स सुमित बारवे, प्रबंधन विभाग और नासिर खान कम्प्यूटर विभाग, थल सैनिक कैम्प, आई.जी.सी. हेतु चयनित हुए हैं।

पीएच.डी. उपाधि

वर्ष 2019-20 में 6 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 43 शोध छात्र पंजीकृत हैं। इनमें से 40 मीडिया विषयों में तथा 3 कम्प्यूटर विषय में पीएच. डी. शोध कार्य कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय से संबद्ध अध्ययन संस्था विभाग

विश्वविद्यालय में कुल 1495 संबद्ध अध्ययन संस्थाएं, कम्प्यूटर पाठ्यक्रम एवं 38 संस्थाएं मीडिया पाठ्यक्रमों का प्रदेशभर में संचालन कर रही हैं। इस वर्ष संस्थाओं की अकादमिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लाइनेक्स विषय पर संकाय विकास कार्यशाला की गई। कार्यशाला के माध्यम से प्रदेश भर की अध्ययन संस्थाओं में अध्यापनरत् शिक्षक लाभान्वित हुए।

बजट (एक दृष्टि में)

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

मांग संख्या - 32 शीर्ष (2220) सूचना तथा प्रचार (आयोजनेत्तर)

(31.01.2019 की स्थिति में)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	शीर्ष	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	(2304) निर्देशन और प्रशासन	21195.28	20628.99	17107.72	12776.67
2	(7248) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार	7000.00	6999.74	5406.30	4263.11
3	(5489) पत्रकारिता पुरस्कार प्रशिक्षण	98.00	96.73	68.20	3.51
4	(8688) म.प्र. सूचना केंद्र, नई दिल्ली	149.35	108.96	147.23	91.50
5	(2822) चलचित्र इकाई की स्थापना	725.00	598.96	672.85	224.41
6	(0994) क्षेत्र प्रचार	1500.00	1482.20	1818.62	1300.59
7	(4065) विशेष अवसरों पर प्रचार	8018.00	7529.28	7112.22	4264.19
8	(0223) प्रकाशन	472.50	370.45	498.18	363.67
9	(1294) वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को सम्मान निधि	120.00	110.95	103.20	100.20
10	(7437) पत्रकारों को लेपटॉप प्रदाय	18.00	5.60	3.20	1.60
11	(0684) कार्यालय भवन निर्माण	500.00	70.00	250.00	-
12	(5620) समन्वित प्रचार-प्रसार	540.00	305.90	436.47	316.18
13	(8808) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	0.01	-	32.00	29.26
14	(0102) अनुसूचित जनजाति उपयोजना (5621) जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	245.00	71.96	181.87	-
15	(0103) अनुसूचित जाति उपयोजना (5621) जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	271.47	79.59	201.85	-
	महायोग (मांग संख्या-32)	**40852.61**	**38459.31**	**34039.91**	**23734.89**

सामान्य प्रशासनिक विषय

प्रतिवेदित अवधि में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 05 सहायक संचालकों की नवीन पद-स्थापना की गई। सहायक संचालक के 11 सीधी भर्ती के रिक्त पदों का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग, इंदौर को भेजा गया। विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पद की पूर्ति का प्रस्ताव पी.ई.बी. को भेजा गया।

विभाग के 02 दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रितों को पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति भी दी गई। प्रतिवेदित अवधि में 08 राजपत्रित अधिकारियों को समयमान वेतनमान का लाभ भी दिया गया।

जनसंपर्क विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के अचल सम्पत्ति के विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों की पदक्रम सूची- 2019 भी प्रकाशित की जा चुकी है।

लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान पेड- न्यूज संबंधी मामले, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सभी समाचार-पत्र, पत्रिकाओं का परिनिरीक्षण और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों की मानीटरिंग के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के कार्यालय में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को 24 घंटे सतत् तैनात किया गया। झाबुआ विधानसभा उप चुनाव के लिये नोडल अधिकारी नामांकित किया गया।

मैग्नीफिसेंट एम.पी-इन्वेस्टर्स समिट, इंदौर के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये इंदौर में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले 2 वाहन चालक को वरिष्ठताक्रमानुसार नियमित वाहन चालक के रिक्त पदों पर समायोजित किया गया।

कर्मचारी-कल्याण

कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति एवं समयमान-वेतनमान दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सभी पात्र कर्मचारियों को उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया गया।

विभागीय कर्मचारी संघ की समस्याओं/ कठिनाइयों, मांगों का यथोचित निराकरण संचालनालय स्तर पर किया गया। शासन स्तर पर निराकृत होने वाली मांगों के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं।

सोशल मीडिया/विभागीय प्रशिक्षण

विभागीय कार्यों एवं दायित्वों का कुशलता एवं दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिये जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों का रिफ्रेशर कोर्स, 104वां संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभागीय जेंडर सेल के सदस्यों के लिये प्रशिक्षण, विभिन्न संस्थानों द्वारा दिलाया गया।

महिलाकर्मियों की समस्याओं का निराकरण

महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के संबंध में मुख्यालय पर राजपत्रित महिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है। समिति की अनुशंसाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विभाग में महिलाओं की सर्वाधिक पद-स्थापना मुख्यालय में है। यहाँ महिलाओं के लिए अलग से प्रसाधन की व्यवस्था है। इसी प्रकार अधीनस्थ कार्यालयों में भी महिला कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। राज्य महिला आयोग के प्रचार-प्रसार कार्यों को संपादित करने के लिए एक राजपत्रित अधिकारी को नामांकित किया गया है।

कार्यालय भवन निर्माण

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बैतूल एवं दमोह के लिये विभागीय भवन तैयार कर लोकार्पित करवाये गये।

भाग-5

विभागीय प्रकाशन

जनसंपर्क विभाग द्वारा मासिक ''मध्यप्रदेश संदेश'' नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा साप्ताहिक रोजगार और निर्माण का नियमित प्रकाशन भी हो रहा है।

भाग-6

उपसंहार

जनसंपर्क विभाग का प्रमुख कार्य शासन की जन-कल्याणकारी नीतियों, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा जनता के हित में सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, आकाशवाणी, समाचार-पत्र/पत्रिकाओं, प्रकाशनों, क्षेत्र प्रचार के पारम्परिक और आधुनिक माध्यमों के साथ ही सोशल-डिजिटल मीडिया के जरिये जन-सामान्य तक पहुँचाना है। लोकसभा निर्वाचन-2019 एवं शासन की गतिविधियों का संचालनालय सहित प्रदेश के सभी जिला जनसंपर्क कार्यालयों द्वारा सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

सूचनाओं के विस्तार के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिला स्तर के समाचारों की उपलब्धता की दृष्टि से विभागीय वेबसाइट www.mpinfo.org., समाचार-पत्र, पत्रिकाओं की क्लीपिंग के लिये www.mpnewsarch.org, जिलों की खबरों के लिये डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल www.dprmpinfo.org सतत् कार्यशील है। इन साइटों को मौजूदा परिवेश में नवीनतम स्वरूप देकर मोबाइल उपयोगी के साथ यूजर्स फ्रेन्डली भी बनाया गया।

श्री पी. नरहरि, आयुक्त जनसम्पर्क ने जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम को संबोधित किया।

गांधीजी
मध्यप्रदेश में ....
भोपाल